टेलीफोन उपभोक्ताओं के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही किये जाने में विलम्ब

6369. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन द्वारा उपभोक्ताओं के आवेदन पत्रों पर तत्काल विचार नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) टेलीफोन स्थानांतरित किये जाने/एस०टी०डी० सुविधा प्रदान किए जाने अथवा समाप्त किये जाने के संबंध में महीने-वार और महाप्रबंधक-वार कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(घ) कितने आवेदन पत्रों पर उनके प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर कार्यवाही की गई है; और

(ड़) इस कार्य के लिए कितने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (ड़) सूचना एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

संसद-सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्र

6370. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संसद-सदस्यों द्वारा संचार मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों को लिखे गए पत्रों का अंतिम उत्तर नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) 1 जुलाई, 1992 से 30 मार्च, 1994 तक कितने संसद-सदस्यों के पत्र प्राप्त हुए हैं तथा कितने पत्रों का अब तक अंतिम उत्तर नहीं दिया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में जिम्मेदारी निश्चित की है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

Delay in Finalising Tenders

6371. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what are the details of steps taken to reduce the delay in finalising tenders of department of telecommunications; and

(b) what are the reasons for the delay in finalising tenders in which indigenous producers participate?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Tender procedure has been streamlined. The steps taken are as under:

(i) A checklist has been prepared to reduce procedural delays.

(ii) The time schedule has been fixed for each activity involved in tendering. Delays are monitored and steps taken to reduce them.

(b) Normally the cases are settled within time frame fixed.

फैक्स (एफ०ए०एक्स०) सुविधा

6372. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सभी जिला मुख्यालय में फैक्स की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात में ऐसे जिला मुख्यालयों की संख्या कितनी है जहां यह सुविधा प्रदान की जाएगी; और

(घ) राज्य में ऐसे जिला मुख्यालयों की संख्या कितनी है और जहां 31 मार्च, 1994 तक यह सुविधा उपलब्ध है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां। सरकार की देश के सभी जिला मुख्यालयों में फैक्स सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिये)**

(ग) दमन एवं सिलवासा संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों सहित चार जिला मुख्यालयों में अभी फैक्स सुविधा प्रदान की जानी है।

(घ) 31.3.94 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य में 17 जिला मुख्यालयों में फैक्स सुविधा उपलब्ध है।

विवरण

अनुबंध

जिन जिला मुख्यालयों में फैक्स सुविधा प्रदान नहीं की गई है उनकी राज्य वार संख्या

क्रम सं॰	राज्य का नाम	संख्या
1.	अरूणाचल प्रदेश	12
2.	असम	121
3.	बिहार	4
4.	गुजरात	4
5.	हरियाणा	3
6.	हिमाचल प्रदेश	2
7.	जम्मू एंड कश्मीर	10
8.	केरल	1
9.	मध्य प्रदेश	10
10.	महाराष्ट्र	3
11.	मणिपुर	7
12.	मेघालय	4
13.	मिजोरम	2
14.	नागालैण्ड	6
15.	उड़ीसा	15
16.	पंजाब	7
17.	राजस्थान	7
18.	सिक्किम	3
19.	उत्तर प्रदेश	3
20.	पश्चिम बंगाल	3

विशेष टिप्पणी: शेष राज्यों के जिला मुख्यालयों में फैक्स सुविधा उपलब्ध है।

21.	संघ राज्य क्षेत्र	पोर्ट ब्लेयर, पांडीचेरी तथा कवारती को छोड़ कर सभी जिला मुख्यालयों में प्रदान की जानी है।

पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल घोटाला

6373. **श्री सोम पाल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 1994 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि पंजाब में जगराव शहर में अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कालें चोरी से की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच के आदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस कदाचार में अंतर्ग्रस्त लोगों के नाम क्या हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) देश के अन्य भागों में भी हो रहे इस प्रकार के गोलमाल को रोकने के लिए सरकार कौन से स्थाई उपाय कर रही है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां।

(ख) विभागीय तौर पर प्रारंभिक जांच की गई थी। तथापि समाचार में उल्लिखित आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर के देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आकस्मिक निरीक्षण तेज कर दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों की सहायता ली जा रही है। अनाचार के मामलों से निपटने के लिए, महानगरीय शहरों में केन्द्रीय जांच ब्यूरों के विशेष जांच-कक्ष स्थापित किए जाने हैं। लाइनों के विपणन आदि जैसे अनाचार के उत्प्रेरकों और अनाचार से लाभ प्राप्त करने वालों के विरूद्ध कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और आगे संशोधन करने के उद्देश्य से लोक सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

Extra Charges on STD/ISD by Five Star Hotels

6374. DR. ISHWAR CHANDRA GUPTA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Five Star Hotels charges